

न्यूज़ ड्रडे

नेशनल कौंसिल ऑफ़ एप्लाइड रिसर्च (NCAER) ने भूमि अभिलेख और सेवा सूचकांक (Land Records and Services Index: N-LRSI) जारी किया

○ यह सूचकांक वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई **NCAER भूमि नीति पहल (NLPI)** का एक भाग है। इस पहल का उद्देश्य आर्थिक अनुसंधान, नीति विश्लेषण और भूमि संबंधित व्यवस्थित डेटा के अंतराल को समाप्त करना है।

> NCAER एक आर्थिक नीति थिंक टैंक है।

> दो चरणों (वर्ष 2019 और वर्ष 2021) के मध्य राष्ट्रीय औसत में 16.2% का सुधार हुआ है। यह अभिलेखों और पंजीकरण प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण में उल्लेखनीय प्रगति दर्शाता है। (इन्फोग्राफिक देखें)।

○ **भू अभिलेखों का डिजिटलीकरण क्यों महत्वपूर्ण है?**

> भारत में सभी दीवानी मुकदमों में से भूमि संबंधी विवाद का हिस्सा 60-70% है।

> ऐसे विवाद स्वामित्व के लिए असुरक्षा उत्पन्न करने के साथ-साथ ऋण और अन्य आर्थिक लेन-देन में अवरोध उत्पन्न करते हैं।

> ये विवाद व्यापार परिवेश में असुरक्षा की भावना उत्पन्न करते हैं। इसके अतिरिक्त ये नए निवेश को हतोत्साहित करते हैं और शासन के समक्ष चुनौती उत्पन्न करते हैं।

○ **भू-अभिलेखों के डिजिटलीकरण में चुनौतियां**

> अपूर्ण/अप्राप्य डेटा।

> भूखंड (**Plots**) संख्या-क्रम की पहचान करना।

○ इससे पूर्व, स्वामित्व योजना (ग्रामों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण) (Survey of Villages and Mapping with Improved Technology in Village Areas: SVAMITVA scheme) ग्रामीण भारत के अब तक गैर-मानचित्रित तथा आवासित हिस्सों में भू-स्वामित्व प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष (International Year of Millets) घोषित किया

○ बांग्लादेश, केन्या आदि के साथ भारत द्वारा प्रायोजित "वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित" करने के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया है।

○ इस कदम का उद्देश्य:

> मोटे अनाज (कदन्न) के सेवन से संबद्ध पोषण और स्वास्थ्य संबंधी लाभों तथा प्रतिकूल एवं परिवर्तनशील जलवायु परिस्थितियों में कृषि के लिए उनकी उपयुक्तता के बारे में जागरूकता का प्रसार करना और नीतिगत कार्रवाई को निर्देशित करना।

> मोटे अनाज से संबंधित अनुसंधान एवं विकास तथा विस्तार सेवाओं में निवेश के लिए ध्यान आकर्षित करना।

○ मोटे अनाज छोटे बीज वाली घास का एक समूह है। इसे व्यापक रूप से मानव खाद्य के लिए खाद्यान्नों के रूप में तथा पशुओं हेतु चारे के रूप में उगाया जाता है।

> वर्तमान में भारत में उत्पादित की जाने वाली मोटे अनाज की तीन प्रमुख फसलें हैं यथा: ज्वार (**sorghum**), बाजरा (**pearl millet**) और रागी (**finger millet**)।

○ मोटे अनाज के संवर्धन के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय:

> "पोषक तत्वों-से युक्त अनाज" के रूप में मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए गहन कदन्न संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा पहल (**INSIMP**)।

> उच्च **MSP** के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। वर्ष 2014 & 15 से वर्ष 2020 तक रागी के लिए MSP में 113 प्रतिशत, बाजरे के लिए 72 प्रतिशत और ज्वार के लिए 71 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

> एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटे अनाज) का संचालन किया जा रहा है।

Digital push

The Land Record Services Index was formulated in 2019 with the broad objective of gauging the extent of digitization of land records.

Top 5 states	Score	Change in rank
Madhya Pradesh	80.2	No change ↔
West Bengal	78.5	4 ↑
Odisha	77.2	1 ↓
Maharashtra	70.9	1 ↓
Tamil Nadu	70.3	No change ↔

Bottom 5 states	Score	Change in rank
Sikkim	8.8	No change ↔
Assam	18.5	1 ↓
Kerala	21.4	1 ↑
Manipur	22.3	No change ↔
Gujarat	35.3	2 ↓

Source: NCAER

Historical Efforts towards Digitisation of Land Records

Strengthening of Revenue Administration and Updating of Land Records (SRA & ULR) (1987-88)

Computerisation of Land Records (CLR) (1988-89)

National Land Records Modernisation Programme (NLRMP)/ Digital India - Land Records Modernisation Programme (DI-LRMP) 2008/2016

उच्चतम न्यायालय के अनुसार स्थानीय निकायों में अनुसूचित जाति (SC)/अनुसूचित जनजाति (STs) व अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए सीटों का आरक्षण, 50% से अधिक नहीं हो सकता

○ यह निर्णय महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, 1961 की धारा 12(2)(C) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया गया है। इसके अंतर्गत राज्य को स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBCs) को 27% आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

> उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि, अनुसूचित जातियों (SC) और अनुसूचित जनजातियों (ST) के लिए "संवैधानिक" आरक्षण के विपरीत, OBC के लिए आरक्षण केवल "सांविधिक" आधार पर प्रदान किया गया है।

○ न्यायालय ने निर्देश दिया कि OBC के लिए स्थानीय निकायों में सीटें आरक्षित करने से पूर्व राज्य द्वारा त्रिपक्षीय परीक्षण (triple test) का अनुपालन किया जाना चाहिए। त्रिपक्षीय परीक्षण, वर्ष 2010 के कृष्णा मूर्ति और अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य वाद में SC की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित किया गया था।

> स्थानीय निकायों में पिछड़ेपन के निहितार्थ और प्रकृति में समकालीन सुदृढ़ अनुभवजन्य जांच के संचालन के लिए एक समर्पित आयोग की स्थापना करना;

> आयोग की अनुशंसाओं के संदर्भ में प्रावधानित स्थानीय निकाय के लिए आवश्यक आरक्षण का अनुपात निर्दिष्ट करना; तथा

> आरक्षण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग को मिलाकर आरक्षित कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

○ संविधान के अनुच्छेद 243D में पंचायतों में SC, ST और महिलाओं के लिए पंचायत सदस्य या अध्यक्ष के पद हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

> इसके अतिरिक्त, यह अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं को नागरिकों के पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का उपबंध करने का अधिकार भी प्रदान करता है।

Millets: an approach for sustainable agriculture and healthy world

Food Security

- Sustainable food source for combating hunger in changing world climate
- Resistant to climatic stress, pests and diseases

Nutritional Security

- Rich in micronutrients like calcium, iron, zinc, iodine etc.
- Rich in bioactive compounds
- Better amino acid profile

Safety from diseases

- Gluten free: a substitute for wheat in celiac diseases
- Low GI: a good food for diabetic persons
- Can help to combat cardiovascular diseases, anaemia, calcium deficiency etc.

Economic security

- Climate resilient crop
- Sustainable income source for farmers
- Low investment needed for production
- Value addition can lead to economic gains

भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के मध्य अकादमिक सहयोग पर विनियमन का प्रारूप जारी किया गया है

○ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा यूजी.सी. (भारतीय और विदेशी उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच संयुक्त डिग्री, दोहरी डिग्री और संयुक्त कार्यक्रम के लिए अकादमिक सहयोग) विनियमन 2021 का प्रारूप तैयार किया गया है।

- ज्ञातव्य है कि इसकी घोषणा बजट 2021 में पहले ही की जा चुकी थी।
- यह सहयोग के 3 तरीकों का प्रस्ताव करता है:



○ विदेशी सहयोग के लाभ:

- भारतीय संस्थानों में सर्वोत्तम प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित होगा तथा उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा और रैंकिंग में सुधार होगा।
- उन सामग्रियों और साधनों तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिनका स्थानीय रूप से अभाव है। साथ ही, उभरते वैज्ञानिकों के लिए विशेषज्ञों आदि के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।

○ हाल ही में प्रारंभ की गई अन्य पहलें:

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अंतर्गत
 - उन सामग्रियों और साधनों तक पहुंच सुनिश्चित होगी, जिनका स्थानीय रूप से अभाव है। साथ ही, उभरते वैज्ञानिकों के लिए विशेषज्ञों आदि के साथ कार्य करने का अवसर प्राप्त होगा।
 - विश्व स्तर के विश्वविद्यालयों को भारत में अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर खोलने की अनुमति प्रदान की जाएगी।
- शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग को बढ़ावा देने के लिए योजना (स्पार्क) **[Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration (SPARC) scheme]**- यह योजना भारतीय संस्थानों और विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के मध्य शैक्षिक एवं अनुसंधान आधारित सहयोग को सुविधाजनक बनाने हेतु आरंभ की गई है।

ईज़ ऑफ़ लिविंग इंडेक्स (Ease of Living Index: EoLI) और नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (Municipal Performance Index: MPI) जारी किए गए

○ इन दोनों सूचकांकों को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था।

- EoLI में III शहरों ने भाग लिया और III नगरपालिकाओं के लिए MPI जारी किया गया।
- EoLI वस्तुतः एक मूल्यांकन उपकरण है, जो जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के लिए विभिन्न पहलों के प्रभाव का आकलन करता है।
 - यह सूचकांक जीवन स्तर, एक शहर की आर्थिक-क्षमता, स्थिरता और नागरिक धारणा के आधार पर संपूर्ण भारत के प्रतिभागी शहरों के संदर्भ में व्यापक समझ प्रदान करता है।
 - सूचकांक का प्रथम संस्करण वर्ष 2018 में जारी किया गया था।
- इस वर्ष नगरपालिका कार्य निष्पादन सूचकांक (MPI) को पहली बार EoLI के सहायक के रूप में लॉन्च किया गया है।
 - MPI का उद्देश्य भारतीय नगरपालिकाओं का उनके निर्धारित कार्यों के आधार पर कार्य प्रदर्शन का आकलन और विश्लेषण करना है।
 - इसके अंतर्गत 20 विभिन्न क्षेत्र शामिल हैं। ये क्षेत्र हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, जल और अपशिष्ट जल, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) और स्वच्छता, पंजीकरण व परमिट, बुनियादी ढांचा, राजस्व प्रबंधन आदि।

	EoLI	MPI
10 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी	शीर्ष रैंकिंग: बेंगलुरु (प्रथम), पुणे	इंदौर (प्रथम), सूरत और भोपाल।
10 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी	शिमला (प्रथम), भुवनेश्वर	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (प्रथम), तिरुपति और गांधीनगर।

अन्य सुर्खियाँ

झारखंड में "प्रथम परिणाम आधारित बजट" प्रस्तुत किया गया (Jharkhand tables the "First Outcome-Based Budget")	<ul style="list-style-type: none"> ○ परिणाम-आधारित बजट सभी सरकारी कार्यक्रमों के परिणामों की माप करता है और सुनिश्चित करता है कि धन उस प्रयोजन के लिए ही व्यय किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था। ○ इसके अंतर्गत, एक क्षेत्रक विशेष का प्रबंधन करने वाले प्रत्येक मंत्रालय को वित्त मंत्रालय के समक्ष प्रारंभिक परिणाम आधारित बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। इसके पश्चात् वित्त मंत्रालय उन सभी को संकलित करता है। ○ इससे बजट के परिव्यय, उत्पादन और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करने में मदद मिलती है। <ul style="list-style-type: none"> ➤ परिव्यय (Outlay)- वह राशि जो किसी योजना या परियोजना के लिए प्रदान की जाती है। ➤ उत्पाद (Output)- कार्यक्रम की गतिविधियों से सृजित मापनीय उत्पाद, जिसे भौतिक रूप में व्यक्त किया जाता है। ➤ परिणाम (Outcome)- यह 'आउटपुट' मात्र से परे की गणना है। यह वस्तुओं या सेवाओं की गुणवत्ता और प्रभावशीलता को भी शामिल करता है।
फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 (Food Waste Index Report 2021)	<ul style="list-style-type: none"> ○ यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा जारी की गई है। ○ इसके अनुसार, वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कुल खाद्य के 17% के बराबर (लगभग 931 मिलियन टन) खाद्य, व्यर्थ हो गया था। ○ भारत में नष्ट हुए खाद्य की मात्रा 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। यह नाइजीरिया की तुलना में कम थी, जहां 189 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खाद्य नष्ट हुआ था। ○ रिपोर्ट के अनुसार खाद्य की बर्बादी को कम करने से खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा। साथ ही, यह जलवायु परिवर्तन की समस्या को भी संबोधित करेगा। इससे धन की बचत होगी और पर्यावरण पर कम दबाव पड़ेगा।
द्वारका एक्सप्रेसवे परियोजना (Dwarka Expressway project)	<ul style="list-style-type: none"> ○ भारतमाला परियोजना के अंतर्गत निर्मित यह मार्ग दिल्ली में द्वारका को गुडगांव से जोड़ता है। इसे भारत का पहला ग्रेड-सेपरटेड अर्बन एक्सप्रेसवे (grade-separated urban expressway) कहा जाता है। <ul style="list-style-type: none"> ➤ इसमें भारत की सबसे लंबी (3-6 किमी) और साथ ही सबसे चौड़ी (आठ लेन) शहरी सड़क सुरंग (अर्बन रोड टनल) होगी। ○ भारतमाला परियोजना आर्थिक गलियारों, इंटर कॉरिडोर और फीडर मार्गों, राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार (National Corridor Efficiency Improvement) इत्यादि के प्रभावी हस्तक्षेपों के माध्यम से महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक अंतरालों की पूर्ति करने वाले राजमार्ग क्षेत्रक के लिए एक छत्र कार्यक्रम है।